

आर्थिक संवृद्धि पर प्रभाव

(Impact on Economic Growth)

कुछ अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि आगे आने वाले वर्षों में आयु-संरचना में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कई एशियाई देश लाभान्वित होंगे क्योंकि उनमें बच्चों की जनसंख्या के सापेक्ष कार्यकारी जनसंख्या का विस्तार होगा जिससे उनमें निर्भरता अनुपात (dependency ratio) कम हो जाएगी। आयु-संरचना में परिवर्तनों का आर्थिक संवृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा जैसाकि निम्नलिखित विवेचन में स्पष्ट है :

1. आयु-संरचना में परिवर्तन के दौरान बचत दर में वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार, देश को जो जनांकिकी लाभ प्राप्त होगा वह स्वतः ऐसे पूंजी संसाधन पैदा करेगा जिनकी देश को निवेश के लिए आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि चालू उपभोग के बाद निवेश के लिए जो अधिशेष बचता है वह वास्तविक श्रम शक्ति तथा श्रम शक्ति के बाहर के लोगों के बीच अनुपात पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, अन्य बातें समान रहने पर, देश की जनसंख्या में श्रमिकों का गैर-श्रमिकों से अनुपात जितना अधिक होगा, निवेश के लिए अधिशेष भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए कम निर्भरता अनुपात वाली अवधियों में उच्च संवृद्धि होगी (वर्तमान नई पूंजी के निवेश की प्रेरणा हो)। इसके विपरीत, अधिक निर्भरता अनुपात वाली अवधियों में निवेश के लिए कम अधिशेष प्राप्त होने की संभावना होगी जिससे संवृद्धि दर भी कम ही रहेगी।

2. जननक्षमता में कमी के परिणामस्वरूप और अधिक स्त्रियां श्रम बाजार में आएंगी जिससे आर्थिक गतिविधियों का प्रसार होगा। स्त्रियों के श्रम शक्ति में प्रवेश में बड़ी बाधाएं उच्च जननक्षमता तथा बच्चों की देख-रेख में बिताया गया समय रहे हैं। जननक्षमता में कमी होने पर स्त्रियों के लिए आर्थिक गतिविधियों में अधिक समय बिताना संभव हो पाता है। इससे आर्थिक संवृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

3. जब बच्चों की संख्या सीमित होती है तो लोग अपने स्वास्थ्य पर अधिक निवेश करने की स्थिति में होते हैं जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे परिवार को आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं।

4. बच्चों की संख्या में कमी होने पर शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं पर सार्वजनिक व्यय में कटौती करना संभव होता है जिससे सरकार अधिक उत्पादक गतिविधियों पर ज्यादा खर्च व निवेश कर सकती है।

के. एस. जेम्स ने कुछ अध्ययनों के निष्कर्षों का उल्लेख किया है जिनसे यह सिद्ध होता है कि जनांकिकी चरों तथा आर्थिक परिणामों के बीच घनिष्ठ धनात्मक संबंध हैं।¹⁶ उदाहरण के लिए 78 एशियाई व गैर-एशियाई देशों के अध्ययन से ब्लूम एवं विलियमसन (1988) को यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि कार्यकारी जनसंख्या में वृद्धि का आर्थिक संवृद्धि पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनके अनुमान अनुसार, पूर्वी एशियाई देशों के तीव्र आर्थिक विकास में जनांकिकी लाभ का लगभग एक-तिहाई योगदान रहा है। बहरमैन व उनके सहयोगियों द्वारा 1999 में किए गए कई देशों के अध्ययन से भी आयु-संरचना व आर्थिक परिणामों में घनिष्ठ संबंध स्पष्ट होता है। 1980 से स्कैन्डिनेवियन देशों के आंकड़ों का अध्ययन करके 2001 में प्रकाशित अपने अध्ययन में एंडरसन को भी आर्थिक संवृद्धि तथा कार्यकारी जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध प्राप्त हुआ है। ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने 2003 तथा 2006 में प्रकाशित अपने लेखों में 1996 से 2000 के बीच कई देशों के आंकड़ों का अध्ययन करके भारत तथा चीन में आयु संरचना में परिवर्तनों तथा आर्थिक संवृद्धि में धनात्मक संबंध पाया है।

परन्तु कुछ अन्य अध्ययनों के परिणाम इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते। उनके अनुसार, आयु संरचना में परिवर्तन का आर्थिक संवृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए, नवनीथम ने 2002 के अपने अध्ययन में पाया कि जहाँ दक्षिण-पूर्व एशिया में आयु-संरचना का आर्थिक संवृद्धि पर धनात्मक प्रभाव पड़ा था वहाँ दक्षिण एशियाई देशों में इस प्रकार का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। ब्लूम व उनके सहयोगियों के 2003 के अध्ययन से भी स्पष्ट होता है कि लैटिन अमेरिकी देशों में आयु-संरचना में परिवर्तन का आर्थिक संवृद्धि पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

भारतीय जनसंख्या की आयु-संरचना

(Age Structure of India's Population)

सारणी 8.4 में भारत के मुख्य राज्यों में आयु वर्ग अनुसार 1961 तथा 2001 में जनसंख्या का वितरण दिया गया है।

सारणी 8.4 : मुख्य राज्यों में आयु वर्ग अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत वितरण (1961 तथा 2001)

राज्य	0-14		15-59		60+	
	1961	2001	1961	2001	1961	2001
आंध्र प्रदेश	39.54	32.07	54.23	60.32	6.23	7.61
बिहार	42.32	41.54	52.07	52.01	5.62	6.45
गुजरात	42.89	32.84	52.17	60.25	4.94	6.91
हरियाणा	उ.न.	35.99	उ.न.	56.49	उ.न.	7.52
कर्नाटक	42.16	31.91	52.11	60.40	5.73	7.69
केरल	42.64	26.08	51.53	63.44	5.84	10.48
मध्य प्रदेश	40.82	38.21	54.02	54.66	5.16	7.14
महाराष्ट्र	40.67	32.14	54.07	59.12	5.27	8.74
उड़ीसा	39.10	32.23	55.23	58.50	5.67	8.27
पंजाब	43.57	31.39	49.87	59.57	6.56	9.03
राजस्थान	42.66	40.10	52.19	53.12	5.14	6.78
तमिलनाडु	37.61	26.96	56.79	64.15	5.60	8.89
उत्तर प्रदेश	40.50	40.83	53.22	52.10	6.29	7.07
पश्चिम बंगाल	40.93	33.28	54.06	59.60	5.01	7.12
भारत	41.0	35.4	53.3	57.1	5.6	7.5

उ.न. का अर्थ है 'आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं'।

स्रोत : K.S. James, "Glorifying Malthus : Current Debate on 'Demographic Dividend' in India", *Economic and Political Weekly*, June 21, 2008, Table 1, p. 66.

जैसाकि सारणी 8.4 से स्पष्ट है, कई भारतीय राज्यों में 1961 से 2001 के बीच चार दशकों में 0-14 से 15-59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या के वितरण में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं⁷ :

1. गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों में 1961 से 2001 के दौरान 0-14 आयु वर्ग में जनसंख्या 10 प्रतिशत बिन्दु तक की गिरावट हुई है। इसके विपरीत, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान जैसे राज्यों में 3 प्रतिशत बिन्दु भी कम गिरावट हुई है।

2. कार्यकारी आयु वर्ग 15-59 वर्ष में केरल में 1961 से 2001 के बीच चार दशकों में जनसंख्या में 10 प्रतिशत बिन्दु से अधिक वृद्धि हुई है। जिन अन्य राज्यों में कार्यकारी आयु वर्ग में जनसंख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देती है वे हैं आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब तथा तमिलनाडु। महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल भी इन राज्यों के काफी करीब हैं और उनमें कार्यकारी आयु वर्ग में जनसंख्या में लगभग 5 प्रतिशत बिन्दु वृद्धि दिखाई देती है। इनमें से अधिकतर राज्यों में लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या कार्यकारी आयु वर्ग में है। इसके विपरीत, कई उत्तरी राज्यों जैसे बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान में 1961 से 2001 के बीच चार दशकों में कार्यकारी आयु वर्ग में जनसंख्या में नाममात्र प्रतिशत वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में तो कार्यकारी आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात कम हुआ है।

जैसाकि सारणी 8.4 तथा ऊपर दिए गए विवेचन से स्पष्ट है, विभिन्न राज्यों में जननक्षमता परिवर्तनों में चलन अलग-अलग रहे हैं। इससे यह आशा बंधती है कि भारत को आगे आने वाले कुछ दशकों तक जनांकिकी लाभ मिलते रहेंगे। दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों एवं पश्चिमी बंगाल में जल्दी जननक्षमता परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कम निर्भरता दर प्राप्त हो वहाँ उत्तरी राज्यों को जनांकिकी लाभ मिलना अभी शेष है। उत्तरी राज्यों में आयु-संरचना में परिवर्तन कम वर्ष बाद ही हो पाएँगे जनांकिकी लाभ से फायदा संभवतः एक दशक बाद।⁸